23 फीसद धूल और मिट्टी के कण, 17 फीसद हिस्सा वाहनों का उत्सर्जन, 16 प्रतिशत जनरेटर आदि का उत्सर्जन, सात फीसद औद्योगिक उत्सर्जन और 12 फीसद पराली व अन्य को जलाने से उत्सर्जन जिम्मेदार है दिल्ली की हवा के जहरीले होने के लिए।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 6 नवंबर 2019

पंजाब में पराली जलाने पर एक ही दिन में 52 किसान गिरफ्तार

कार्रवाई ▸ सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद बढ़ी सख्ती, पंजाब, हरियाणा और उप्र में मंगलवार को 850 किसानों पर केस दर्ज

कसा शिकंजा, 1531 किसानों पर लगाया 42 लाख 75 हजार का जुर्माना

जेएनएन, जालंधर

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भी किसानों ने मंगलवार को जमकर पराली जलाई। वहीं, पंजाब सरकार ने भी पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ प्रदेश भर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की। एक ही दिन में 371 किसानों के खिलाफ केस दर्ज कर 52 को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, हरियाणा में 313 और उत्तर प्रदेश में 166 किसानों पर मामला दर्ज हुआ है।

पंजाब के मुख्य सचिव करन अवतार सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मंगलवार को सभी जिलों के अधिकारियों की खिंचाई की। इसके बाद तमाम अधिकारी देर शाम तक फील्ड में जमे रहे। हालांकि उनसे संपर्क नहीं हो सका, लेकिन देर रात तक विभाग के अधिकारी किसानों पर की गई कार्रवाई के आंकड़े जुटाते रहे।

1346 किसानों पर ठोका 38 लाख का जुर्माना : दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुख्य सचिव को तलब किया हुआ है। प्रदेश सरकार को कोर्ट में यह बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या-क्या कदम उठाए हैं। यही वजह है कि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) भी सख्त हो गया है और दो दिन में उसने 1346 किसानों पर शिकंजा कसकर 38 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। यह अभी वसूला नहीं गया है।

किसानों ने अफसर को बनाया बंदी : मानसा में पराली को आग लगाने की रिपोर्ट बनाने गए पटवारी वेद प्रकाश और ब्लॉक खेतीबाड़ी के एक अफसर को गांव भैणीबाघा के किसानों ने भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां की अगुआई में बंदी बना लिया। इसी तरह गांव हीरेवाला में पराली जलाने की रिपोर्ट बनाने गए पटवारी का किसानों ने घेराव किया।

हरियाणा में 313 किसानों पर दर्ज हुआ केस : हरियाणा में भी सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए मंगलवार को 313 किसानों पर मामले दर्ज किए हैं। प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा दिए जाने वाले आंकड़ों के मुताबिक 25 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक 4341 स्थानों पर पराली जलाई जा चुकी थी। इस अवधि में प्रदेश भर में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ 1150 केस पुलिस में दर्ज कराए गए।

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर होगा एक करोड़ जुर्माना : प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली एनसीआर के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया है। प्रदूषण का अलग-अलग ग्रेड निर्धारित कर उसी के हिसाब से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि तय कर दी है। सीपीसीबी के मानकों का उल्लंघन करने पर उद्योगों को अधिकतम एक करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि बोर्ड कार्यालय में जमा करानी होगी।

उप्र में भी 166 किसानों पर मामला दर्ज : उत्तर प्रदेश में सख्ती अपनाते हुए अब तक कुल 586 किसानों को नोटिस जारी कर 166 किसानों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। इसके अलावा 185 किसानों पर 4,75,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। लापरवाही बरतने के आरोप में एक लेखपाल को निलंबित और एक पर विभागीय कार्यवाही की गयी है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में पिछले वर्ष की तुलना में 46.9 प्रतिशत कमी आयी है।

पीएम ने उत्तर भारत में प्रदूषण पर बैठक की अध्यक्षता की

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर भारत में प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इससे पहले पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने रविवार और सोमवार को दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के उच्च अधिकारियों से चर्चा की थी। पीएमओ ने ट्वीट किया, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रदूषण के कारण पैदा हुए हालात पर चर्चा हुई।' पीएमओ के अनुसार मोदी ने पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में चक्रवात की स्थिति पर भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री द्वारा चक्रवात 'महा' के लिए तैयारी की समीक्षा किए जाने से एक दिन पूर्व राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने गुजरात, महाराष्ट्र तथा दमन एवं दीव में तैयारियों की समीक्षा की थी। छह नवंबर की रात यह चक्रवात द्वारका और दीव पहुंचने वाला है। जिला प्रशासनों को अलर्ट पर रखा गया है और मछली पकड़ने की गतिविधियां फिलहाल टाल दी गई हैं।

तिल के तेल की दो बूंद सोख लेगी वायु प्रदूषण

जागरण संवाददाता, मेरठ : चरक संहिता के 28वें अध्याय में आत्रेय कहते हैं कि वायु ही आयु है। इस महाग्रंथ ने वायु प्रदूषण से बचाने के लिए बड़ा मंत्र दिया, जिस पर अमल कर जहरीली गैसों से बचा जा सकता है। तिल के तेल की दो बूंद नाक में डालने से कार्बन कणों व पीएम-10 जैसे सूक्ष्म कण फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाएंगे। महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की डॉ. निधि शर्मा ने 150 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया है। चरक संहिता में वर्णित प्रतिमर्श नस्य (नाक से दवा डालकर इलाज) पर शोध करते हुए मरीजों को एलर्जिक रानाइटिस व सांस की बीमारियों से राहत मिली। मेरठ में मानक 60 से पांच गुना यानी 300 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक वायु प्रदूषण पहुंच चुका है। सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन एवं मोनोऑक्साइड के सूक्ष्म कण नाक की नलियों में सूजन के जरिए अस्थमा का मरीज बना देते हैं। सीओपीडी के मरीजों को सांस का अटैक आ जाता है। नाक में तेल डालने पर प्रदूषित सूक्ष्म कण इसमें चिपक जाते हैं। ऐसे में प्रदूषण फेफड़ों तक नहीं पहुंचेगा।

> नस्य में प्रयुक्त तेल नाक के अंदर एक प्रतिरक्षा परत बनाता है। जिसे प्रतिमर्श कहते हैं। हानिकारक कण नाक के जरिए फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाते हैं। यह नाक के अंदर की श्लेष्मिक झिल्ली को भी ताकत देता है। सप्ताह तक नस्य कर्म के बाद मरीजों को प्राणायाम भी कराया गया। माहभर में फेफड़ों में बड़ा सुधार मिला।
>
> **-डॉ. निधि शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मेरठ**

हरभजन की पीएम से अपील हमें प्रदूषण से बचाइए

हरभजन सिंह। फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से उत्तर भारत में वायु प्रदूषण कम करने के लिए कोई ठोस तरीका ढूंढने की अपील की है। बता दें कि हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया था। कुछ स्थानों पर यह 999 तक चला गया, जो आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी और स्कूल मंगलवार तक बंद कर दिए गए थे।

हरभजन ने ट्विटर पर एक वीडियो के माध्यम से यह अपील की है। उन्होंने कहा, 'मैं उत्तर भारत में प्रदूषण के बारे में बात करना चाहता हूं। हम सभी इसका कारण हैं और मैं भी इनमें शामिल हूं। हम जो गाड़ियां चलाते हैं उससे वातावरण दूषित होता है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों से हमें पता चला है कि पराली जलाने से हवा काफी दूषित हो जाती है।' उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक बच्चे या उस जगह पर रहने वाले लोगों के लिए खतरनाक है। ऐसा भी पता चला है कि अगर यही हालात रहे तो उम्र सात से दस साल कम हो जाएगी। हमें इस पर कार्रवाई करनी होगी। हरभजन ने कहा, 'मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूं। मैं दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे पीएम मोदी से मिलें। आपको किसानों और हर जीव-जंतु को ध्यान में रखकर ऐसा उपाय ढूंढना होगा जिससे सबका भला हो। मैं चाहूंगा कि यह बैठक जल्द से जल्द हो।' इस ऑफ स्पिनर ने कहा, 'प्रधानमंत्री जी कृपा करके इसको अपना समय दीजिए और हमें रास्ता दिखाइए कि भारत को स्वच्छ के साथ स्वस्थ भारत कैसे बनाया जा सकता है। अपने वातावरण को साफ सुथरा बनाने के लिए हम सब आपके साथ हैं। हम अपनी तरफ से हर तरह का योगदान देंगे।'

न्यूज गैलरी

आतंकियों की घुसपैठ नाकाम, पाक सेना को दिया करारा जवाब

पुंछ : पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार सुबह पुंछ जिले के शाहपुर किरनी सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए भारी गोलाबारी की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम बना दिया। जानकारी के अनुसार, सुबह करीब सात बजे पाक सेना ने एकाएक पुंछ के शाहपुर किरनी सेक्टर में गोलाबारी शुरू कर दी। पाक सेना ने पहले सेना की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाया और उसके बाद रिहायशी क्षेत्रों पर मोर्टार दागना शुरू कर दिए। गोलाबारी की आड़ में पाक सेना भारतीय क्षेत्र में आतंकियों के दल को घुसपैठ करवाने का प्रयास कर रही थी, जिसे सेना के जवानों ने विफल कर दिया। इसके साथ ही पाक सेना को गोलाबारी का करारा जवाब भी दिया। इस गोलाबारी में किसी नुकसान की सूचना नहीं है। (जासं)

दंतेवाड़ा के मुनगा में मुठभेड़ दो वर्दीधारी नक्सली ढेर

दंतेवाड़ा : छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के मुनगा जंगल में मंगलवार को डिस्ट्रिक रिजर्व गार्ड (डीआरजी) की टीम के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई। इसमें जवानों ने दो वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया। घटनास्थल से दोनों के शव, दो बंदूक और नक्सली सामग्री बरामद की गई है। दोनों एक-एक लाख रुपये के इनामी थे। एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव ने बताया कि मौके की तलाशी लेने पर दो नक्सलियों के शव, दो बंदूक, डेटोनेटर, वायर, रेडियो, दवाएं और बड़ी मात्रा में नक्सली साहित्य बरामद हुआ है। मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त हिड़मा मंडावी एलजीएस (लोकल गुरिल्ला स्क्वॉड) सदस्य और हुंगा मंडावी मिलिशिया प्लाटून कमांडर के रूप में की गई है। (नईदुनिया)

एयरपोर्ट पर युवक बना रहा था स्टंट का वीडियो, गई जान

कुशीनगर : उप्र स्थित कुशीनगर के निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के रनवे पर लाइव स्टंट कर रहे एक युवक की मौत हो गई। वह कार की डिक्की पर बैठकर तेज रफ्तार का वीडियो शेयर कर रहा था। युवक का नाम 28 वर्षीय अमन मिश्र है जो देवरिया के गांव सकरापार का निवासी है। अमन ममेरे भाई रवि मिश्र के साथ कसया निवासी मित्र के घर आया था। दिन में तीन बजे अपने पांच दोस्तों संग कार से एयरपोर्ट पर पहुंचा। अन्य साथी कार में बैठे थे। एक युवक लगभग 180 किमी प्रति घंटे की गति से कार चला रहा था। अमन पीछे डिक्की पर बैठकर वीडियो लाइव शेयर कर रहा था। इसी दौरान कार लहराई और युवक रनवे पर गिर गया। दोस्त उसे सीएचसी लेकर पहुंचे तो चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। (जासं)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के पूर्व एमडी गिरफ्तार

भविष्य निधि घोटाला

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

एपी मिश्रा। (फाइल फोटो)

बिजली इंजीनियरों और कर्मचारियों के भविष्य निधि घोटाले में उप्र पावर कारपोरेशन के तत्कालीन निदेशक वित्त और सचिव ट्रस्ट के बाद आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पावर कारपोरेशन के पूर्व एमडी एपी मिश्र को भी गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार तड़के मिश्र को हिरासत में लेकर ईओडब्ल्यू ने दिनभर पूछताछ की। इस बीच शक्ति भवन स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट के कार्यालय में लगातार दूसरे दिन छानबीन कर कई और अहम दस्तावेज भी ईओडब्ल्यू ने कब्जे में लिए हैं।

डीजी ईओडब्ल्यू डॉ. आरपी सिंह का कहना है कि पीएनबी हाउसिंग में भी भविष्य निधि की रकम नियम विरुद्ध निवेश की गई थी। उन्होंने दावा किया कि पूर्व एमडी एपी मिश्र के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। मिश्र पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी रहे हैं। सपा शासन के दौरान नियमों में बदलाव कर एपी मिश्र को प्रबंध निदेशक के पद पर सेवा विस्तार दिया जाता रहा। ट्रस्ट के चेयरमैन होने के नाते पावर कारपोरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष संजय अग्रवाल (वर्तमान में केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के सचिव) समेत कई और बड़ों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। मिश्र की गिरफ्तारी के बाद अब अन्य की भी मुश्किलें बढ़नी तय है।

ईओडब्ल्यू ने मंगलवार तड़के 4.30 बजे मिश्र को अलीगंज स्थित उनके आवास से हिरासत में लेकर दिनभर पूछताछ की। डीजी ईओडब्ल्यू के अनुसार शुरुआती जांच में मिश्र की संलिप्तता सामने आई है। पूर्व एमडी ने ही 2016 में भविष्य निधि की रकम पीएनबी हाउसिंग में निवेश करने को मंजूरी दी थी, जबकि पीएनबी हाउसिंग में निवेश भी नियम विरुद्ध था। जांच में यह भी सामने आया है कि 15 मार्च 2017 को निजी कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफसीएल) से कोटेशन लिया गया था। अगले दिन 16 मार्च को दो और निजी कंपनियों से कोटेशन लिए गए और उसी दिन डीएचएफसीएल में भविष्य निधि की रकम निवेश किए जाने की अनुमति दे दी गई।

16 मार्च 2017 को तत्कालीन एमडी एपी मिश्र ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि 17 मार्च को डीएचएफसीएल को 18 करोड़ रुपये की पहली किस्त आरटीजीएस के जरिये दे दी गई थी। ईओडब्ल्यू की जांच में यह भी सामने आया है कि डीएचएफसीएल को दिए गए अप्रूवल को ट्रस्ट बोर्ड की मंजूरी दिलाने के लिए 22 मार्च 2017 को दो साल बाद पहली बैठक बुलाई गई थी।

पांच सदस्यीय बोर्ड की बैठक में पावर कारपोरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष संजय अग्रवाल, एमडी एपी मिश्र, निदेशक वित्त सुधांशु त्रिवेदी, महाप्रबंधक व सचिव ट्रस्ट प्रवीण कुमार तथा निदेशक कार्मिक सत्यप्रकाश पांडेय (दिवंगत) मौजूद थे। वास्तव में 22 मार्च को हुई बैठक को लिखा-पढ़ी में 24 मार्च को होना दिखाया गया। ईओडब्ल्यू ने मंगलवार को ट्रस्ट कार्यालय में की गई छानबीन के दौरान 22 मार्च को बुलाई गई बोर्ड बैठक के पुख्ता प्रमाण हासिल किए हैं। बैठक की नोट शीट भी मिली है, जिसमें पूर्व एमडी के भी हस्ताक्षर हैं। बताया गया कि ओवरराइटिंग करके बैठक की तारीख को 24 मार्च किया गया था। ईओडब्ल्यू कई और तथ्यों की गहनता से छानबीन कर रही है।

आखिर किस हड़बड़ी में थे एपी मिश्र : ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने एपी मिश्र से पूछताछ के बाद जब दोबारा ट्रस्ट कार्यालय के दस्तावेज खंगाले तो सवाल उठते चले गए। एपी मिश्र ने 16 मार्च 2017 को अपना इस्तीफा दे दिया था, जो 23 मार्च 2017 को मंजूर हुआ था।

ईओडब्ल्यू अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर मिश्र इतनी हड़बड़ी में क्यों थे? इस्तीफा देने के बाद मिश्र भविष्य निधि की रकम निजी कंपनी को दिलाने के लिए लगातार किन कारणों से प्रयासरत थे? बोर्ड बैठक की तारीख में खेल किन कारणों से और किसके इशारे पर किया गया था। जांच की आंच कई बड़ों तक भी पहुंच सकती है।

कराया जाएगा आमना-सामना भी : ईओडब्ल्यू ने घोटाले में गिरफ्तार आरोपित उप्र पावर कारपोरेशन के तत्कालीन निदेशक वित्त सुधांशु त्रिवेदी और महाप्रबंधक व सचिव ट्रस्ट प्रवीण कुमार गुप्ता को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी। ईओडब्ल्यू दोनों आरोपितों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के बाद एपी मिश्र से उनका आमना-सामना भी कराएगी।

सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता को परीक्षा देने से रोकने पर तीन प्रोफेसर सस्पेंड

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी

▸ हरियाणा के रेवाड़ी का मामला पीड़िता को मर्सी चांस के लिए डीसी ने लिखा पत्र

▸ सितंबर 2018 में एक युवती से हुआ था सामूहिक दुष्कर्म

सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता को परीक्षा से वंचित रखने के मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट पर उच्च शिक्षा विभाग ने तीनों प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है। दूसरी ओर उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखकर पीड़िता को मर्सी चांस देने का आग्रह किया है।

सितंबर 2018 में जिले के एक गांव निवासी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। छात्रा एक राजकीय कॉलेज में बीएससी प्रथम वर्ष में पढ़ती है। 16 मई को पीड़िता को परीक्षा केंद्र में अलग से बैठकर पेपर देने की व्यवस्था की गई थी, परंतु 18 मई को पीड़िता जब दूसरा पेपर देने गई तो केंद्र अधीक्षक व दो अन्य शिक्षकों ने उसे अलग बैठकर पेपर देने से रोक दिया था। पीड़िता की मां ने तीनों पर अपमानित करने का आरोप भी लगाया था।

रिपोर्ट के आधार पर किया निलंबित : पीड़िता की मां की शिकायत पर उपायुक्त ने उप पुलिस अधीक्षक, डाइट प्राचार्य, महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी और महिला थाना एसएचओ की कमेटी गठित की थी। कमेटी में जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में तीनों प्रोफेसर को दोषी करार दिया गया था।

> पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा। परीक्षा में न बैठने की जानकारी मिलते ही एक कमेटी गठित कर जांच कराई गई थी। छात्रा को परीक्षा देने से रोकने वाले तीनों प्रोफेसर निलंबित हो गए हैं। अब दोबारा से पीड़िता से परीक्षा दिलाने के लिए मंगलवार को ही विवि के कुलपति को पत्र लिखा गया है।
>
> **- यशेंद्र सिंह, उपायुक्त रेवाड़ी।**

उपायुक्त ने उच्च शिक्षा विभाग को तीनों को निलंबित करने की सिफारिश की थी। उपायुक्त की सिफारिश पर सहायक प्रोफेसर सुषमा यादव, अजीत सिंह व जगत सिंह को निलंबित कर दिया है।

उपायुक्त ने जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद 20 अगस्त को ही इंदिरा गांधी विवि की रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर छात्रा को परीक्षा देने का दोबारा मौका देने के लिए कहा था। इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। मंगलवार को अब आइजीयू के वाइस चांसलर को पत्र लिखकर मर्सी चांस देने के लिए कहा गया है।

कश्मीर में नाबालिगों को हिरासत में लेने के आरोपों की जांच के आदेश

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के किशोर न्याय समिति को नाबालिगों को हिरासत में रखने के आरोपों की नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया। राज्य से अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद से सुरक्षा बलों द्वारा नाबालिगों को हिरासत में लिए जाने का आरोप है। जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने किशार न्याय समिति (जुवेनाइल जस्टिस कमेटी) से कहा कि वह अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करे। इस मामले पर अब तीन दिसंबर सुनवाई होगी।

पीठ ने कहा कि इन आरोपों की नए सिरे से जांच की आवश्यकता है क्योंकि समिति की पहले की रिपोर्ट समयाभाव की वजह से शीर्ष अदालत के आदेश के अनुरूप नहीं थी। शीर्ष अदालत कश्मीर घाटी में गैरकानूनी तरीके से नाबालिगों को कथित रूप से हिरासत में लिए जाने का मुद्दा उठाने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

इससे पहले किशोर न्याय समिति ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पांच अगस्त से अब तक 9 से 17 साल के 144 नाबालिगों को सुरक्षा कारणों से हिरासत में लिया गया, जिनमें से 142 को बाद में रिहा कर दिया गया। बाकी के दो नाबालिगों को किशोर गृह में भेज दिया गया है।

बाल अधिकार कार्यकर्ता इनाक्षी गांगुली और सांता सिन्हा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की किशार न्याय समिति से उन आरोपों का पता लगाने और उन पर रिपोर्ट सौंपने को कहा था जिनमें कहा गया था कि राज्य में गैरकानूनी तौर पर बच्चों को हिरासत में लिया गया।

▸ सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के किशोर न्याय समिति से यथाशीघ्र रिपोर्ट भी मांगी

▸ पिछले महीने समिति ने सुरक्षा कारणों से 144 नाबालिगों को हिरासत में लिए जाने की दी थी जानकारी

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

कश्मीर में फोन, इंटरनेट पर पाबंदी को अवैध बताया

कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की तरफ से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने जम्मू-कश्मीर में फोन और इंटरनेट सेवाओं पर रोक को अवैध और असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि 90 दिन बाद भी कश्मीर घाटी में लैंडलाइन, मोबाइल, इंटरनेट, और एसएमएस सेवाएं चालू नहीं हुई हैं, जिससे मीडिया को कामकाज करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

किश्तवाड़ में हुए आतंकी हमलों की जांच करेगी एनआइए

राज्य ब्यूरो, जम्मू

भाजपा नेता अनिल परिहार व उनके भाई की हत्या की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने किश्तवाड़ में बीते एक साल के दौरान हुई अन्य आतंकी वारदातों की जांच का भी जिम्मा भी संभाल लिया है। एनआइए ही अब आरएसएस पदाधिकारी चंद्रकांत शर्मा व उनके अंगरक्षक की हत्या, जिला उपायुक्त किश्तवाड़ के अंगरक्षक से हथियार छीनने और पीडीपी के स्थानीय नेता को परिवार समेत बंधक बनाने ओर उनके अंगरक्षक से हथियार छीनने के मामले की जांच करेगी।

संबंधित अधिकारियों ने बताया कि राज्य प्रशासन के आग्रह पर ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन मामलों की जांच एनआइए को सौंपी है। अब तक यह जांच राज्य पुलिस कर रही थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि चंद्रकांत शर्मा की हत्या, पीडीपी नेता और जिला उपायुक्त के अंगरक्षकों से हथियार छीनने और रामबन में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों का संबंध बीते साल पहली नवंबर को किश्तवाड़ में हुई भाजपा नेता अनिल परिहार और उनके भाई की हत्या में शामिल आतंकियों से था। ये सभी आतंकी एक ही गुट के हैं। पुलिस ने बीते एक साल के दौरान लगभग आठ से 10 आतंकियों को भी पकड़ा है।

अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआइए ने चंद्रकांत शर्मा, जिला उपायुक्त किश्तवाड़ के अंगरक्षक से हथियार छीनने और पीडीपी नेता को बंधक बनाने के मामले में तीन अलग-अलग एफआइआर दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। चंद्रकांत शर्मा व उनके अंगरक्षक की इसी साल नौ अप्रैल को आतंकियों ने जिला अस्पताल किश्तवाड़ में हत्या कर दी थी। इससे पूर्व आठ मार्च को आतंकियों ने जिला उपायुक्त किश्तवाड़ के अंगरक्षक दिलीप कुमार से उसके घर से ही उसकी सरकारी असाल्ट राइफल छीनी थी। इसके बाद आतंकियों ने 13 सितंबर को किश्तवाड़ जिला में पीडीपी के जिला प्रधान शेख नासिर के पूरे परिवार को बंधक बनाया और उनके अंगरक्षक से उसकी असाल्ट राइफल लेकर भाग गए थे। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि इन वारदातों में हिजबुल मुजाहिदीन का एक ही गुट शामिल रहा है। इसलिए एक ही जांच एजेंसी को जांच का जिम्मा सौंपने का फैसला किया गया है।

गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर में स्थिति की समीक्षा की

नई दिल्ली, प्रेट्र : गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने के तीन महीने बाद मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। यह गृह मंत्री और नव गठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के शीर्ष नागरिक और पुलिस अधिकारियों के बीच पहली बैठक है। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय के भल्ला एवं गृह मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम और पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा हालात खासतौर से मोबाइल फोन नेटवर्क पर से प्रतिबंध हटाए जाने के बाद की स्थिति के बारे में शाह को बताया। बहरहाल, अभी यह नहीं पता चला है कि बैठक में नेताओं को रिहा करने के बारे में चर्चा की गई है या नहीं। ये नेता पांच अगस्त से हिरासत में हैं। हिरासत में लिए गए नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर में जनजीवन अब भी बाधित है। स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान अभी पूरी तरह नहीं खुले हैं जबकि बाजार और प्रतिष्ठान कुछ अवधि के लिए खुल रहे हैं।

अब शहीदों और महापुरुषों के नाम पर होंगी कश्मीर की सड़कें

तैयारी

भवनों, चौराहों व बाजार के नाम भी बदले जाने की तैयारी, शुरुआत शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर से हो सकती है

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कश्मीर घाटी की सड़कों और चौराहों के नाम अब आतंकवाद से लड़ने के दौरान शहीद हुए स्थानीय अधिकारियों और महापुरुषों के नाम पर रखने की तैयारी है। इसके अलावा राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की आवाज बुलंद करने वाले लोगों और अन्य शहीदों के नाम पर कुछ बाजार और भवनों के नाम किए जा सकते हैं।

नाम में बदलाव की शुरुआत शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर से हो सकती है। इसका नाम देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखे जाने की चर्चा है। फिलहाल, यह स्टेडियम नेशनल कांफ्रेंस के संस्थापक और एकीकृत जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. शेख अब्दुल्ला के नाम पर है। इसके अलावा श्रीनगर एयरपोर्ट का नाम भी बदल सकता है।

शाह ने किया था शहीदों को याद करने का आह्वान : यहां यह बताना असंगत नहीं होगा कि जुलाई में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने श्रीनगर दौरे के दौरान निर्देश दिया था कि कश्मीर में शहीद पुलिसकर्मियों को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। शहीदों के नाम पर गली-मोहल्लों का नामकरण होना चाहिए। चौराहों और महत्वपूर्ण इमारतों को उनके नाम को समर्पित किया जाए ताकि आम लोग उनकी कुर्बानी और योगदान को समझ सकें। इससे कश्मीरियों में राष्ट्रवाद की भावना मजबूत होगी और अलगाववादी तत्व कमजोर होंगे।

पटेल की पुण्यतिथि पर हो सकती है घोषणा : आधिकारिक स्तर पर कोई भी अधिकारी वादी में नाम बदलने की योजना की पुष्टि करने को तैयार नहीं है। हालांकि, स्थानीय प्रशासनिक हलकों में शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि 15 दिसंबर को सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर स्टेडियम का नाम लौह पुरुष के नाम पर हो जाएगा। इस स्टेडियम में सिर्फ दो बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच हुए हैं। पहला मैच 13 अक्टूबर 1983 को भारत बनाम वेस्टइंडीज और दूसरा मैच 9 सितंबर 1989 को इंडिया व ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था।

श्रीनगर के अलावा अन्य शहरों में भी होगा बदलाव : सूत्रों ने बताया कि श्रीनगर के अलावा घाटी के अन्य शहरों और कस्बों में भी कई जगहों के नाम बदलते हुए उनके नाम आतंकवाद के साथ लड़ते हुए शहीद हुए पुलिस अधिकारियों, कर्मियों व कश्मीर में राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के लिए शहीद हुए गणमान्य नागरिकों के नाम पर आधारित होंगे। इनमें लेफ्टिनेंट उमर फैयाज और डीएसपी अयूब पंडित भी शामिल हैं।

बदला कश्मीर, न हिंसा-न पत्थरबाजी

राज्य ब्यूरो, जम्मू : राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी को लगभग 92 दिन बीत चुके हैं और इसका असर वादी में आतंकी गतिविधियों पर भी नजर आ रहा है। न आतंकी हिंसा-न पत्थरबाजी। स्थानीय युवकों की आतंकी संगठनों में भर्ती भी अपने निम्न स्तर पर जा पहुंची है। मुठभेड़ में मारे जाने वाले आतंकियों के जनाजे पर न राष्ट्रविरोधी नारे लगाती अब भीड़ नजर आती है और न हवा में गोलियां दागते उनके साथी आतंकियों के वीडियो नजर आ रहे हैं। स्थानीय भर्ती में कमी से हताश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ अब बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी आतंकियों को कश्मीर में खून खराबे के लिए घुसपैठ कराने का हर संभव मौका तलाश रही है। राज्य गृह विभाग के मुताबिक, इस साल पहली जनवरी से 30 अक्टूबर तक लगभग 40 स्थानीय लड़के ही आतंकी बने हैं। वर्ष 2018 में पहली जनवरी से 31 मार्च तक ही 40 लड़के आतंकी बन चुके थे, जबकि पूरे साल के दौरान आतंकी बनने वाले कुल लड़कों की संख्या करीब 70 थी। आतंकरोधी अभियानों में अहम भूमिका निभा रहे एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि यहां बहुत सी अफवाहें चलती रहती हैं। आपको कोई बताएगा कि बीते तीन माह के दौरान 100 लड़के आतंकी बन गए हैं तो कोई 500 बताएगा, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। पांच अगस्त के बाद से पूरे कश्मीर में हमारे मुताबिक, करीब 11 लड़के गायब हुए और इन सभी के परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया। इनमें छह वापस अपने घरों को लौट आए। एक तीन दिन पहले सोपोर में पकड़ा गया है।

लोकतंत्र बहाली को राजनीतिक बंदियों की हो रिहाई : नेकां

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : नेशनल कांफ्रेंस ने मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक और राजनीतिक गतिविधियों को पूरी तरह बहाल करने के लिए मुख्यधारा से संबंधित राजनीतिक बंदियों की रिहाई का आग्रह किया है। मंगलवार को जारी एक बयान में नेकां ने कहा है कि पांच नवंबर को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और एकीकृत जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित राज्यों में विभाजित करने के तीन माह पूरे हो चुके हैं। इसके बाद भी अभी तक इंटरनेट और मोबाइल फोन की निर्विघ्न सेवा बहाल नहीं हुई है। यहां तक कि एसएमएस सेवा भी बंद है। प्रशासनिक पाबंदियों से कश्मीर में कई लोगों के समक्ष रोजगार का संकट पैदा हो चुका है। सैकड़ों लोगों को हिरासत में रखा गया है। इनमें से कई लोगों को राज्य के बाहर की जेलों मे स्थानांतरित किया गया है, जिससे उनके परिजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के तीन पूर्व सीएम डॉ. फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पांच अगस्त से ही बंद हैं।

मां को ऐसी जगह शिफ्ट करें, जहां ठंड से बचाव के अच्छे इंतजाम हों : इल्तिजा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने मंगलवार को राज्य प्रशासन से उसकी मां को ऐसी जगह स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है, जहां ठंड से बचाव का पूरा बंदोबस्त हो। इल्तिजा ने अपनी मां के स्वास्थ्य की चिंता जताते हुए जिला उपायुक्त श्रीनगर को एक पत्र भी लिखा है। इल्तिजा ने लिखा है कि अगर मेरी मां को कुछ होता है तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने मंगलवार को एक ट्वीट में लिखा है कि मैं कई बार अपनी मां की सलामती के लिए चिंता जता चुकी हूं।